नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 145
दि. 27.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

निवेश के नाम पर 'फाल्कन' का फंदा, 792 करोड़ की ठगी का बड़ा चेहरा गिरफ्तार

हैदराबाद। निवेश के सुनहरे सपने दिखाकर हजारों लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी हड़पने वाले बहुचर्चित 'फाल्कन घोटाले' में तेलंगाना की अपराध अन्वेषण विभाग (CID) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फाल्कन ग्रुप के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी विकास कुमार सखारे को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी न केवल इस बहुस्तरीय आर्थिक अपराध की परतें खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, बल्कि इससे देशभर में फैले निवेश ठगी के नेटवर्क में भी हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, सखारे इस पूरे घोटाले का एक अहम किरदार था, जिसने निवेशकों को भ्रमित करने और धन जुटाने की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।

तेलंगाना सीआईडी की अतिरिक्त महानिदेशक चारू सिन्हा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि विकास कुमार सखारे केवल एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि वह इस पूरे फर्जी निवेश मॉडल का एक प्रमुख संचालक था। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों का विश्वास जीतने, उन्हें झूठे आश्वासन देने और बड़ी रकम जमा कराने में केंद्रीय भूमिका निभाई। उसके खिलाफ लंबे समय से शिकायतें दर्ज थीं और जांच के दौरान मिले ठोस सबूतों के आधार पर उसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी उन हजारों पीड़ितों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है, जिन्होंने इस योजना में अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी।

इस घोटाले का तरीका बेहद सुनियोजित और तकनीकी रूप से जटिल था। आरोपियों ने 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग' नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया, जो देखने में पूरी तरह वैध और पेशेवर लगता था। इस ऐप के माध्यम से लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे किसी सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना में पैसा लगा रहे हैं। निवेशकों को भरोसा दिलाया गया कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और उन्हें निश्चित समय में आकर्षक रिटर्न

मिलेगा। ऐप की डिजाइन, इंटरफेस और प्रस्तुतिकरण इतना विश्वसनीय था कि आम लोग ही नहीं, बल्कि कई शिक्षित और अनुभवी निवेशक भी इसके जाल में फंस गए।

जांच में सामने आया कि इस ऐप और उससे जुड़ी कंपनियों के माध्यम से हजारों लोगों से भारी रकम जुटाई गई। 'कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड' सहित अन्य संबंधित कंपनियों के जरिए कुल 7,056 निवेशकों से लगभग 4,215 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। यह रकम देश के विभिन्न हिस्सों से जुटाई गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई स्थानीय स्तर की ठगी नहीं थी, बल्कि एक संगठित और राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ आर्थिक अपराध था। इन निवेशकों में छोटे व्यापारी, नौकरीपेशा लोग, सेवानिवृत्त कर्मचारी और गृहिणियां तक शामिल थीं, जिन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने की उम्मीद में इस योजना में पैसा लगाया था।

हालांकि, जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस कुल राशि में से 792 करोड़ रुपये सीधे तौर पर गबन कर लिए गए। यह रकम 4,065 निवेशकों से जुटाई गई थी, जिन्हें बाद में कोई रिटर्न नहीं मिला और उनका निवेश पूरी तरह डूब गया। आरोप है कि विकास कुमार सखारे ने कंपनी के प्रबंध निदेशक अमर दीप कुमार और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस पूरी योजना को संचालित किया। उन्होंने निवेशकों को झूठे वादों और आकर्षक योजनाओं के माध्यम से लुभाया और जब पर्याप्त धन जमा हो गया, तो धीरे-धीरे निवेशकों से संपर्क तोड़ लिया।

इस घोटाले की शुरुआत तब उजागर हुई जब निवेशकों को समय पर रिटर्न मिलना बंद हो गया और उन्होंने कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीड़ितों ने साइबराबाद पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता और इसमें शामिल भारी रकम को देखते हुए इसे आगे की जांच के लिए तेलंगाना सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी ने विस्तृत जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड जुटाए, जिससे इस पूरे घोटाले की साजिश का खुलासा हुआ।

जांच एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और तेलंगाना निवेशक संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। फिलहाल, विकास कुमार सखारे से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि इस घोटाले के अन्य आरोपियों और मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि सखारे से मिली जानकारी के आधार पर फरार मुख्य आरोपी अमर दीप कुमार और अन्य सहयोगियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सकेगा।

इस घोटाले का दायरा केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं है। जांच में यह भी सामने आया है कि फाल्कन ग्रुप और उसके निदेशकों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। यह दर्शाता है कि यह एक व्यापक और संगठित नेटवर्क था, जिसने देशभर में लोगों को निशाना बनाया। इस नेटवर्क ने तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिससे इसकी पहचान करना और इसे पकड़ना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया।

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह लगातार नए और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को आसानी से भ्रमित किया जा सकता है, खासकर जब उन्हें अधिक मुनाफे का लालच दिया जाता है। ऐसे मामलों में आम लोगों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता और विश्वसनीयता की पूरी जांच करें।

सीआईडी की यह कार्रवाई न केवल इस घोटाले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है, जो निवेश के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। जांच एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हजारों निवेशकों की उम्मीदें अब जांच एजेंसियों पर टिकी हैं कि वे इस घोटाले की पूरी सच्चाई सामने लाएं और दोषियों को सजा दिलाएं। साथ ही, यह भी उम्मीद की जा रही है कि लूटी गई रकम का पता लगाकर उसे निवेशकों को वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा। यह मामला न केवल एक आर्थिक अपराध है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के विश्वास और भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बेहतर जीवन की उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई इस योजना में लगाई थी।

सूरत नगर निगम: स्वाति देसाई की नौकरी बरकरार रखने और भर्ती में अनियमितताओं पर चर्चा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम में स्मीयर अस्पताल के गठन के बाद नए कर्मचारियों की भर्ती की गई। इनमें कक्षा 4, कक्षा 3, तकनीकी कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ की तत्काल भर्ती की गई। इसके साथ ही, मेडिकल कॉलेज से तत्काल स्वीकृति प्राप्त करके कर्मचारियों की भर्ती करना आवश्यक हो गया। इस स्थिति में, लाग्गागिया और चाचा-चाची, पिता-पुत्र के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। इसी भर्ती में, स्वाति देसाई, जो वर्तमान में डीएम कमिश्नर के पद पर हैं, लगभग चालीस कर्मचारियों के साथ बिना किसी भर्ती प्रक्रिया के क्लर्क के रूप में शामिल हुईं। इसके बाद, जब उन्हें अवसर मिला, तो सूरत नगर निगम में सचिव के पद के लिए उनका चयन हो गया। और कुछ वर्षों बाद, वे पिछले 3 वर्षों से सूरत नगर निगम में डीएम कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं।

शून्य त्रुटि विज्ञापन

सूरत नगर निगम की नीतियों और नियमों के अनुसार, कार्मिक अधिकारी, सहायक आयुक्त और उप आयुक्त (गैर-तकनीकी) कर्मचारियों/अधिकारियों के पास एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है। यह एक निर्धारित योग्यता है। कार्मिक अधिकारी और सहायक आयुक्तों को आमतौर पर उप आयुक्तों में शामिल किया जाता है, क्योंकि उनके पास

एलएलबी की डिग्री होती है। क्या स्वाति देसाई ने सूरत नगर निगम में कार्यभार संभालने से पहले एलएलबी की पढ़ाई पूरी की थी या उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद एलएलबी की पढ़ाई की? यह जांच का विषय है। सूरत नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसी चर्चा है कि स्वाति देसाई ने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है।

स्वाति देसाई ने इस शर्त पर अपना इस्तीफा वापस ले लिया कि उन्हें किसी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात नहीं किया जाएगा और वे केवल अपने पसंदीदा विभागों में ही काम करेंगी तथा लेखा का काम उन्हीं के पास रहेगा। अंततः उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और एमएनपी को दबाव डालकर पद पर बनी रहीं। सूरत एमएनपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी अधिक बेरोजगारी के बीच, जहां अनेक योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं, स्वाति देसाई को पद पर बनाए रखा गया है?

यहां सवाल यह है कि क्या कोई गॉडफादर स्वाति देसाई को गुपचुप तरीके से बचा तो नहीं रहा है और कहीं वह अपने स्वार्थ के लिए ऐसा तो नहीं कर रहा है? दरअसल, कई सवाल उठते हैं, लेकिन उनके जवाब देने के लिए एमएनपी के पदाधिकारी या उच्च अधिकारी फिलहाल चुप रहने की नीति अपना रहे हैं और आपके और मैरी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं।

ट्रैफिक नियम तोड़े तो 'कटेंगे नंबर', बार-बार गलती पर हमेशा के लिए छिन सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

नई दिल्ली। देश में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या और ट्रैफिक नियमों की लगातार हो रही अनदेखी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि जल्द ही देश में 'ग्रेडेड ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली' लागू की जाएगी, जिसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों के लाइसेंस पर अंक आधारित निगरानी रखी जाएगी। यह नई व्यवस्था ड्राइविंग लाइसेंस को केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का प्रमाणपत्र बना देगी, जिसमें हर चालक के व्यवहार का रिकॉर्ड दर्ज होगा।

नई प्रणाली के अनुसार, प्रत्येक ड्राइवर के लाइसेंस के साथ एक निश्चित संख्या में अंक (पॉइंट्स) जुड़े होंगे। जैसे ही चालक किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करेगा—जैसे रेड लाइट जंप करना, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना, सीट बेल्ट न पहनना, गलत दिशा में वाहन चलाना या मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करना—उसके खाते से अंक काट लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड से सीधे जुड़ी रहेगी। इसका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि चालकों को नियमों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि यदि कोई चालक बार-बार नियम तोड़ता है और उसके सभी अंक समाप्त हो जाते हैं, तो

उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्वतः छह महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं होगा। यदि इसके बाद भी चालक अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता और दोबारा गंभीर उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि वह व्यक्ति भविष्य में कभी भी वैध रूप से वाहन चलाने के लिए पात्र नहीं रहेगा।

यह नई व्यवस्था देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, भारत में हर वर्ष लगभग 1.8 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की त्रासदी का प्रतीक है, जिनके अपने इस लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन हादसों में मरने वालों में लगभग 72 प्रतिशत लोग 18 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं, जो देश की सबसे सक्रिय और उत्पादक आबादी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण मानवीय लापरवाही है। तेज गति से वाहन चलाना, शराब के नशे में ड्राइविंग करना, मोबाइल फोन का उपयोग करना और ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी करना ऐसी गलतियां हैं, जो अक्सर घातक साबित होती हैं। नई अंक आधारित प्रणाली इन गलतियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इससे चालकों को अपने लाइसेंस खोने का वास्तविक खतरा महसूस होगा।

सरकार का यह कदम केवल सख्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत की व्यवस्था भी शामिल है। 'पीएम राहत योजना' के तहत अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के बाद पहले सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सके और पैसे की कमी के कारण उसकी जान खतरे में न पड़े। यह सुविधा देश की किसी भी सड़क पर हुई दुर्घटना के लिए लागू होगी और इसे सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। नई ग्रेडेड लाइसेंस प्रणाली के लागू होने से ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली में भी बड़ा बदलाव आएगा। अब केवल चालान काटना ही उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक उल्लंघन का स्थायी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों की पहचान करना आसान होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। यह प्रणाली पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रणाली विकसित देशों में पहले से सफलतापूर्वक लागू है और वहां इससे सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। भारत में भी इसके लागू होने से लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। जब चालकों को यह पता होगा कि हर गलती का सीधा असर उनके लाइसेंस पर पड़ेगा, तो वे अधिक सतर्क और जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाएंगे।

सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब देश में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और सड़क नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। इस स्थिति में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। नई प्रणाली न केवल चालकों को अनुशासित बनाएगी, बल्कि सड़क पर सभी लोगों—पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और अन्य वाहन चालकों—की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।

मुंबई पुलिस की ताकत में ऐतिहासिक इजाफा, 1290 हाई-टेक वाहनों से सुरक्षा व्यवस्था को मिली नई रफ्तार

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26 फरवरी 2026 को एक भव्य समारोह में मुंबई पुलिस को 1290 अत्याधुनिक वाहनों का नया बेड़ा सौंपा। नरीमन पॉइंट पर आयोजित इस कार्यक्रम में जैसे ही इन नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई, वैसे ही मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत हो गई। यह केवल वाहनों का वितरण नहीं था, बल्कि पुलिसिंग को तकनीक और गति के साथ जोड़ने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाना और आम नागरिकों को सुरक्षा का मजबूत भरोसा देना है।

इन नए वाहनों में 633 चार पहिया वाहन और 657 दुपहिया वाहन शामिल हैं। चार पहिया वाहनों में आधुनिक स्कॉर्पियो और अर्मेनिया जैसे शक्तिशाली और तेज वाहन शामिल हैं, जबकि दोपहिया वाहन विशेष रूप से संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तेजी से पहुंचने के लिए तैयार किए गए हैं। यह बेड़ा मुंबई पुलिस की परिचालन क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा और शहर के हर कोने तक पुलिस की पहुंच को और अधिक तेज और प्रभावी बनाएगा। इन गाड़ियों की सबसे खास बात यह है कि ये केवल परिवहन के साधन नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से तकनीक से लैस मोबाइल कमांड यूनिट की तरह काम करेंगी।

इन सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिससे पुलिस कंट्रोल रूम और गश्ती दल के बीच सीधा और त्वरित संपर्क संभव होगा।

जैसे ही किसी इलाके में कोई अपराध या आपातकालीन स्थिति की सूचना मिलेगी, कंट्रोल रूम तुरंत सबसे नजदीकी वाहन को अलर्ट कर सकेगा। इससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और अपराधियों को पकड़ने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। वर्तमान में मुंबई पुलिस का औसत प्रतिक्रिया समय लगभग 5.30 मिनट है, लेकिन नई तकनीक और संसाधनों के साथ इसे और कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस नए बेड़े का वितरण भी पूरी तरह से रणनीतिक योजना के तहत किया गया है। मुंबई के सभी 90 पुलिस स्टेशनों को समान रूप से इन वाहनों से सशक्त किया गया है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन को 10 नए वाहन दिए गए हैं, जिनमें 5 दोपहिया वाहन, 4 स्कॉर्पियो और 1 अर्मेनिया वाहन शामिल है। इससे न केवल मुख्य सड़कों पर गश्त आसान होगी, बल्कि संकरी गलियों, आवासीय क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में भी पुलिस की पहुंच और अधिक प्रभावी हो सकेगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि शहर का कोई भी हिस्सा पुलिस की निगरानी से दूर न रहे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो राज्य के गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, ने इस अवसर पर कहा कि मुंबई पुलिस पहले से ही देश की सबसे सक्षम और पेशेवर पुलिस बलों में से एक है, और अब इन आधुनिक संसाधनों के साथ इसकी क्षमता वैश्विक स्तर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन वाहनों से न केवल अपराध नियंत्रण में सुधार होगा, बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देगी और भविष्य में भी पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।

मुंबई पुलिस के लिए यह नया बेड़ा केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि उनके मनोबल को बढ़ाने वाला भी है। लंबे समय से पुलिस बल को अधिक संसाधनों और आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। कई बार सीमित वाहनों और पुराने संसाधनों के कारण पुलिस को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इन नई गाड़ियों के शामिल होने से पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक आत्मविश्वास और दक्षता के साथ करने में मदद मिलेगी।

मुंबई जैसे महानगर में, जहां हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं और हजारों गतिविधियां एक साथ चलती हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। भीड़भाड़, ट्रैफिक, संकरी गलियां और लगातार बढ़ती जनसंख्या के बीच पुलिस के लिए हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे में यह नया बेड़ा पुलिस के लिए एक मजबूत हथियार साबित होगा, जिससे वे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से पहुंच सकेंगे और स्थिति को नियंत्रित कर सकेंगे।

इन वाहनों के शामिल होने से अपराधियों के मन में भी कानून का डर बढ़ेगा। जब सड़कों पर पुलिस की सक्रिय और तेज उपस्थिति दिखाई देगी, तो अपराध करने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। साथ ही, आम नागरिकों को भी यह भरोसा मिलेगा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस तुरंत उनकी सहायता के लिए उपलब्ध होगी। यह विश्वास और सुरक्षा की भावना किसी भी शहर के विकास और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

मुंबई पुलिस ने भी इस नई उपलब्धि पर अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त किया है। पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश दिया कि एक मजबूत और आधुनिक फ्लीट के साथ अब पुलिस और अधिक तेज और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यह केवल संसाधनों का विस्तार नहीं है, बल्कि पुलिसिंग के पूरे सिस्टम को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह पहल सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। भविष्य में भी इसी तरह के और कदम उठाए जाने की संभावना है, जिससे पुलिस बल को और अधिक सक्षम और आधुनिक बनाया जा सके।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

विवाहेत्तर संबंधों से दरकता विश्वास

हाल ही में सामने आए एक सर्वेक्षण में, यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जीवन साथी की निगरानी के लिये बड़ी संख्या में डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ली जा रही है। तमाम विवाहेत्तर संबंधों की पड़ताल से बड़ी संख्या में शक सही निकल रहे हैं। हालांकि, इस सर्वे के दायरे और उसकी विश्वसनीयता की कसौटी के प्रश्न सामने हैं, लेकिन यह एक कड़वी हकीकत है कि हमारी पारिवारिक संस्था में अविश्वास की सेंध लग रही है। खाओ-पियो मौज करो की पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण से वैवाहिक संस्था की शुचिता को आंच आई है। समाज में अलगाव, तलाक व हिंसक प्रतिशोध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रही सही कसर कथित सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है, जिसने हमारे समाज में वर्जित माने जाने वाले भदेस विषयों को न्यू नॉर्मल बना दिया है। दरअसल, हाल के वर्षों में भारतीय समाज तेजी से संक्रमणकालीन दौर में जा पहुंचा है। कभी जिस रिश्ते को सिरे चढ़ाते वक्त जन्म-जन्मांतर साथ निभाने का वायदा किया जाता था, आज उसी जीवन साथी की निगरानी के लिये डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ली जा रही है। यह दुखद ही है कि जिन जीवन मूल्यों, संयम व शुचिता के रिश्तों के लिये भारत दुनिया में जाना जाता था, वहां आज यौन स्वच्छंदता व विवाहेत्तर संबंधों का दायरा बढ़ रहा है। एक समय था कि भारतीय संयुक्त परिवार की छांव में संयमित व मर्यादित व्यवहार करते थे। बड़ों का अनुशासन मर्यादा की रक्षा करता था। कामकाज का स्वरूप और स्थानीय रोजगार भी जीवन व्यवहार को संतुलित व संयमित करते थे। लेकिन हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव व देश-विदेश में कामकाज के लिये बाहर जाने के बाद व्यक्ति स्वच्छंद व्यवहार करने लगा। यही वजह है कि विदेश में रहने वाले पति या पत्नी के व्यवहार की पड़ताल के लिये डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद लेने के मामले लगातार उजागर हुए हैं। जिसके बाद मुकदमेबाजी, अलगाव व टकराव की खबरें सामने आने लगती हैं।

दरअसल, विगत में भारतीय समाज में व्यक्ति के सार्वजनिक व्यवहार को संयुक्त परिवार व समाज संयमित करता था। लेकिन धीरे-धीरे आर्थिक आत्मनिर्भरता के बाद लोगों ने बड़े-बुजर्गों व समाज के हस्तक्षेप को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। विगत में हमारी फिल्मों व टीवी निर्माताओं ने दर्शकों की भीड़ जुटाने के लिये हमेशा असामान्य वैवाहिक रिश्तों को अपनी कथावस्तु बनाया। इन असामान्य रिश्तों को इस ग्लैमर के साथ पेश किया जाता रहा है कि कालांतर उसका प्रभाव समाज पर नजर आने लगा। आज तो विदेशी धरती से संचालित इंटरनेट व सोशल मीडिया ने तो असामान्य रिश्तों की पराकाष्ठा दर्शा दी। विडंबना यह रही है कि मीडिया ने भी ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को इतनी तरजीह दी कि समाज के एक तबके में असामान्य रिश्तों को सामान्य माना जाने लगा। एक हकीकत यह भी है कि देश पर तमाम विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई होगी, जितनी इंटरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से परोसी जा रही अपसंस्कृति ने विकृतियां पैदा की। नई पीढ़ी ही नहीं, उम्र दराज लोग भी कामदेव के मोहपाश में बंधे वर्जनाओं को लांघने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बालाओं के मोहपाश में बंधकर गांठ का धन गंवाने वालों में बुजुर्गों की संख्या भी कम नहीं है। निस्संदेह, विवाह एक पवित्र बंधन है। जिसका निर्वहन संयम, सहजता, सहयोग, धैर्य और त्याग से ही होता है। लगता है कहीं न कहीं नई पीढ़ी लगातार धैर्य खोती जा रही है। रिश्तों के दीर्घकालिक निर्वहन का मूलमंत्र यही है कि हम जीवन-साथी की छोटी-मोटी कमियों को नजरअंदाज करके सामंजस्य के साथ जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। असामान्य रिश्तों का अल्पकालिक सुख भले ही लुभाता हो, मगर उसकी कीमत परिवार को लंबे समय तक चुकानी पड़ती है। जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों के मन-मस्तिष्क पर भी घातक होता है। यह भी एक हकीकत है कि जब परिवार के विवाद घर की दहलीज लांघते हैं, तो इससे लाभ उठाने वाले पेशेवरों की पूरी बिरादरी मुस्तैद खड़ी होती है। निश्चित ही रिश्तों में छल की प्रवृत्ति भारत में मूल्यों वाली विवाह संस्था के लिये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसका मुकाबला संयम, सहयोग, त्याग व समर्पण जैसे जीवन मूल्यों से ही संभव है। इसका समाधान कोर्ट-कचहरियों में नहीं मिलेगा।

आर्थिक योगदान व पर्यावरण क्षति का हो मूल्यांकन

> "आगन्तुकों की बाढ़ किसी राज्य की सफलता का पैमाना नहीं, बल्कि एक चेतावनी होना चाहिए। यह चेतावनी है संसाधनों के दोहन, अनियोजित शहरीकरण की और उस नीतिगत अंधेपन की है जो श्रद्धा को निवेश समझ बैठा है।

उत्तराखंड सरकार के अनुसार गत वर्ष राज्य में पर्यटकों का आगमन 6 करोड़ पार कर गया, जो कुल आबादी से छह गुना अधिक है। 'इंडिया टूरिज्म कम्पोडियम 2025' के आंकड़ों पर गौर करें तो यह आंकड़ा कोई मायावी नहीं हैं, बल्कि हकीकत है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की परिभाषा के आधार पर ही ये आंकड़े तैयार किये गये हैं। उन्हीं आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 64.6 करोड़ और तमिलनाडु में 30 करोड़ से अधिक पर्यटक पधारे थे। ये भारी-भरकम आंकड़े सरकारी फाइलों में सफलता के प्रमाणपत्र की तरह पेश किए जाते हैं, लेकिन इनकी गहराई में उतरते ही एक गंभीर विरोधाभास भी सामने आता है। अगर किसी प्रदेश में सचमुच आनंद की अनुभूति के लिए इतने पर्यटक आ जायें तो उस प्रदेश का बेड़ापार ही हो जाये! क्या विशाल भीड़ वास्तव में वह 'पर्यटक' है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, या यह केवल एक सांख्यिकीय भ्रम है?

'संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन' के मानक 'पर्यटक' की परिभाषा को इतना व्यापक बना देते हैं कि इसमें श्रद्धा और सैर-सपाटे के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर 24 घंटे से अधिक रुकता है, तो उसे पर्यटक माना जाएगा, चाहे उद्देश्य धार्मिक हो या मनोरंजन। इन्हीं मानकों की ओट में भारतीय राज्य कांवड़ियों और साधुओं को भी 'पर्यटक' की श्रेणी में दर्ज कर लेते हैं। यहीं से उस धारणा को चुनौती देने की आवश्यकता है जो संख्यात्मक बहुलता को आर्थिक समृद्धि का पर्याय मान लेती है। वास्तव में पर्यटक और तीर्थयात्री के उद्देश्य और खर्च करने की क्षमता में मौलिक अंतर होता है। पर्यटक होटलों में रुकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में 'लिक्विड कैश' का संचार

करता है। इसके विपरीत, पारंपरिक तीर्थयात्री अक्सर अपना भोजन साथ लेकर चलते हैं और उनकी यात्रा का उद्देश्य मानसिक शांति होती है, न कि आर्थिक उपभोग।

'प्लेजर टूर' या आनंदमयी यात्रा ही वास्तव में पर्यटन की वह मूल अवधारणा है जो इसे 'तीर्थाटन' से अलग करती है। पर्यटन का मुख्य आधार 'अवकाश' (लीजर) है, जिसे गिल्बर्ट सिगॉक्स ने एक ऐसी मानवीय गतिविधि माना है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मनोरंजन, ज्ञानवर्धन या स्वास्थ्य लाभ के लिए सामान्य परिवेश का त्याग करता है। तीर्थाटन जहां धार्मिक आस्था, कर्तव्य और मोक्ष की भावना से प्रेरित होता है, वहीं 'प्लेजर टूर' का प्राथमिक उद्देश्य मानसिक शांति, भौतिक सुख और व्यक्तिगत खुशी प्राप्त करना होता है।

दरअसल, तीर्थाटन में जहां 'श्रद्धा' सर्वोपरि है, वहीं पर्यटन या 'प्लेजर टूर' जब हम इन दोनों श्रेणियों को एक ही तराजू में तौलते हैं, तो नीतिगत स्तर पर भारी चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां तीर्थाटन का बोलबाला है, वहां की अवसंरचना पर पड़ने वाला दबाव इन करोड़ों नवागन्तुकों की भीड़ से तय होता है, लेकिन उस दबाव को झेलने के लिए मिलने वाला राजस्व उस अनुपात में नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की भीड़ के लिए प्रशासन को सफाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका वित्तीय बोझ करदाताओं की जेब पर पड़ता है, जबकि उस भीड़ से होने वाला प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ न्यूनतम होता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम केवल संख्या गिनने के लिए अपनी पारिस्थितिकी और संसाधनों को दांव पर लगा रहे हैं?

तर्कपूर्ण ढंग से देखें तो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक अवसंरचना भी पूरी तरह भिन्न होती है। एक हाई-वैल्यू पर्यटक को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छता, निजी स्थान और उच्चस्तरीय आतिथ्य की आवश्यकता होती है। यदि किसी गंतव्य पर तीर्थयात्रियों की अनियंत्रित भीड़ होगी, तो वह स्थान वास्तविक पर्यटकों के लिए अपनी अपील खो देगा। इसे 'क्राउडिंग आउट इफेक्ट' कहा जा सकता है, जहां कम खर्च करने वाली भीड़ अधिक खर्च करने वाले पर्यटकों को विस्थापित कर देती है। संवेदनशील हिमालयी राज्यों के लिए यह स्थिति और भी भयावह है। यहां की 'वहन क्षमता' सीमित है। करोड़ों की संख्या कागजों पर अच्छी लग सकती है, लेकिन क्या हमारे पहाड़, हमारी नदियां और हमारे शहर इतने लोगों का कचरा और उनकी जरूरतों का बोझ उठाने में सक्षम हैं?

हमें राजस्व के आंकड़ों का गहन विश्लेषण करना होगा। क्या हम ऐसे आंकड़े सार्वजनिक कर सकते हैं जो यह बताएं कि प्रति व्यक्ति पर्यटक से राज्य को कितनी आय हुई? अक्सर देखा गया है कि जिस राज्य में पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है, जरूरी नहीं कि पर्यटन से होने वाली आय में भी वह राज्य अव्वल हो। केरल जैसे राज्य ने इस मामले में एक अलग लकीर खींची है, जहां संख्या के बजाय 'वैल्यू' पर ध्यान दिया जाता है। वहां तीर्थयात्री भी आते हैं, लेकिन राज्य की ब्रांडिंग 'गॉड्स ओन कंट्री' के रूप में एक विशिष्ट पर्यटक वर्ग को आकर्षित करने के लिए की गई है। इसके उलट, उत्तर भारत के राज्यों में पर्यटन नीति अक्सर 'संख्या आधारित' होकर रह गई है। सांख्यिकीय जादूगीरी का यह आलम है कि यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान तीन अलग-अलग जिलों में रुकता है, तो उसे तीन पर्यटक मान लिया जाता है।

सामयिक परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी पर्यटन नीति को 'परिमाण' से हटाकर 'गुणवत्ता' पर केंद्रित करना होगा। बजट 2026-27 में घोषित 'पर्यटन केंद्रों की रैंकिंग' की योजना तभी सफल होगी जब रैंकिंग के मानदंडों में केवल फुटफॉल (आगंतुकों की संख्या) को ही पैमाना न बनाया जाए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्रति व्यक्ति राजस्व और आगंतुक के अनुभव को भी शामिल किया जाए। तीर्थयात्रियों के लिए अलग प्रबंधन और पर्यटकों के लिए अलग विपणन रणनीति समय की मांग है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक नंगे पांव चलने वाला श्रद्धालु और एक बैकपैक लेकर चलने वाला पर्यटक, दोनों ही हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता के हिस्से हैं, लेकिन आर्थिक नियोजन में दोनों की भूमिकाएं भिन्न हैं।

आगन्तुकों की बाढ़ किसी राज्य की सफलता का पैमाना नहीं, बल्कि एक चेतावनी होना चाहिए। यह चेतावनी है संसाधनों के दोहन, अनियोजित शहरीकरण की और उस नीतिगत अंधेपन की है जो श्रद्धा को निवेश समझ बैठा है।

प्रेरणा

जब गुरु ने पहचानी दिव्य प्रतिभा और तन्ना बन गया अमर गायक

भारत की सांस्कृतिक परंपरा में गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के जागरण और जीवन के रूपांतरण का माध्यम होता है। इस परंपरा ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया, जिनमें एक नाम सदैव अमर रहेगा, और वह नाम है तानसेन। लेकिन तानसेन जन्म से तानसेन नहीं थे। वे एक साधारण बालक थे, जिनका नाम तन्ना था, और उनकी महानता के पीछे सबसे बड़ा कारण उनके गुरु स्वामी हरिदास की कृपा, मार्गदर्शन और दिव्य दृष्टि थी।

बहुत समय पहले, ग्वालियर के निकट स्थित बेहट नामक एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम तन्ना था। वह स्वभाव से बहुत चंचल और निडर था। उसे जंगलों में घूमना, पेड़ों पर चढ़ना और पशु-पक्षियों की आवाज़ों की नकल करना बहुत पसंद था। जब वह जंगल में जाता, तो कभी शेर की दहाड़, कभी कोयल की कूक और कभी गाय की आवाज़ इतनी सजीवता से निकालता कि सुनने वाला भ्रमित हो जाता कि यह वास्तव में कोई पशु ही है। यह सब उसके लिए खेल था, लेकिन वास्तव में यह उसके भीतर छिपी असाधारण प्रतिभा का संकेत था।

एक दिन की बात है। वृन्दावन के महान संत और संगीत के परम ज्ञाता स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे। चारों ओर पेड़ों की हरियाली थी और वातावरण शांत था। तभी अचानक एक जोरदार शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी प्रबल और वास्तविक थी कि सभी शिष्य भयभीत हो गए। कुछ ने इधर-उधर देखना शुरू किया, तो कुछ पीछे हट गए। लेकिन स्वामी हरिदास जी शांत रहे। उनकी अनुभवी दृष्टि ने उन्हें बताया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है।

उन्होंने धीरे-धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए, जहां से आवाज़ आई थी। जब वे पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और वही शेर की दहाड़ निकाल रहा है। स्वामी जी ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने उस बालक के चेहरे पर मासूमियत और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम देखा। उन्होंने उससे प्रेमपूर्वक कहा, "क्या तुम और भी आवाजें निकाल सकते हो?" बालक ने बिना किसी झिझक के कई पशु-पक्षियों की आवाज़ें निकालकर सुनाईं। उसकी आवाज़ में इतनी सटीकता और शक्ति थी कि स्वामी जी आश्चर्यचकित रह गए।

उस क्षण स्वामी हरिदास जी ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह ईश्वर की विशेष कृपा से जन्मा हुआ है और इसके भीतर संगीत की दिव्य शक्ति छिपी हुई है। उन्होंने बालक के पिता से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे इस बालक को अपने साथ वृन्दावन ले जाना चाहते हैं, ताकि उसे संगीत की शिक्षा दे सकें। प्रारंभ में पिता को संदेह हुआ, लेकिन स्वामी जी की महानता और उनके उद्देश्य को समझकर उन्होंने अनुमति दे दी।

इस प्रकार तन्ना का जीवन एक नए मार्ग पर चल पड़ा। वृन्दावन में स्वामी हरिदास जी के सान्निध्य में उसका नया जन्म हुआ। वहां का वातावरण भक्ति, साधना और संगीत से भरा हुआ था। तन्ना ने अपने गुरु की सेवा करते हुए संगीत की बारीकियों को सीखना शुरू किया। स्वामी जी ने उसे केवल स्वर और राग नहीं सिखाए, बल्कि यह भी सिखाया कि संगीत आत्मा की भाषा है। यह ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है।

तन्ना प्रतिदिन घंटों तक अभ्यास करता। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता और रियाज़ करता। उसकी लगन और समर्पण ने धीरे-धीरे उसके स्वर को दिव्यता से भर दिया। उसकी आवाज़ में ऐसी मधुरता और शक्ति आ गई कि उसे सुनने वाला व्यक्ति भावविभोर हो जाता था। समय बीतता गया, और लगभग दस वर्षों की कठोर साधना के बाद वह एक महान गायक बन गया।

स्वामी हरिदास जी ने उसकी इस उपलब्धि को देखकर उसे एक नया नाम दिया — तानसेन। यह नाम केवल एक पहचान नहीं था, बल्कि उसकी साधना, उसकी सिद्धि और उसकी महानता का प्रतीक था। अब वह केवल एक बालक नहीं रहा था, बल्कि वह संगीत का एक उज्ज्वल सितारा बन चुका था।

धीरे-धीरे उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी गायकी को सुनने के लिए दूर-दूर से आने लगे। उसकी आवाज़ में एक अद्भुत आकर्षण था। ऐसा कहा जाता है कि उसके स्वरों में प्रकृति को प्रभावित करने की शक्ति थी। उसकी गायकी में केवल कला नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार थी। आखिरकार उसकी ख्याति मुगल सम्राट अकबर तक पहुंची। अकबर स्वयं कला और संगीत के महान प्रेमी थे। उन्होंने जब तानसेन के बारे में सुना, तो उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। जब तानसेन ने दरबार में पहली बार गाया, तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तानसेन को अपने नवरत्नों में स्थान दिया। यह किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान था।

लेकिन इतनी महानता प्राप्त करने के बाद भी तानसेन ने कभी अपने गुरु को नहीं भुलाया। वे हमेशा कहते थे कि उनकी सारी सफलता का श्रेय उनके गुरु को ही जाता है। वे मानते थे कि गुरु ही वह प्रकाश हैं, जो शिष्य के जीवन को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के उजाले में ले जाते हैं।

तानसेन का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई विशेष प्रतिभा छिपी होती है। लेकिन उस प्रतिभा को पहचानने और उसे सही दिशा देने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। यदि स्वामी हरिदास जी ने तन्ना की प्रतिभा को नहीं पहचाना होता, तो शायद वह एक साधारण बालक बनकर रह जाता। लेकिन गुरु की कृपा ने उसे अमर बना दिया।

यह कथा केवल एक महान गायक की कहानी नहीं है, बल्कि यह गुरु की महिमा, समर्पण की शक्ति और साधना की महानता का संदेश है। यह हमें सिखाती है कि जब गुरु का आशीर्वाद और शिष्य का समर्पण एक साथ मिलते हैं, तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। तन्ना से तानसेन बनने का यह सफर इसी सत्य का सबसे सुंदर उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

नकली-घटिया सामग्री का बढ़ता बाजार कई किलो मिलावटी खोया बरामद

होली निकट आते ही देश भर से ऐसे समाचार आने का सिलसिला कायम हो गया है कि नकली खोया, पनीर या फिर मिलावटी मिठाइयां बरामद। बीते सप्ताह आगरा की एक खबर के अनुसार राजस्थान से लाया गया 1,320 किलो मिलावटी खोया बरामद किया गया। कानपुर से आई एक खबर यह कहती है कि होली और रमजान के पहले 50 लाख रुपये मूल्य के दस हजार किलो पुराने और खराब हो चुके खजूर के पैकेटों पर नए लेबल चिपकाकर उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी थी।

इसी दिन की एक अन्य खबर के मुताबिक कानपुर में ही छह सौ किलो मिलावटी खोया पकड़ा गया। इसके अलावा लगभग दो लाख रुपये से अधिक मूल्य की कटी हुई सुपारी भी जब्त की गई, जिसे मिलावटी पाए जाने पर नष्ट किया गया। बीते दिनों लखनऊ से आई खबर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसमें करीब 13 क्विंटल सड़े-गले और मानव उपयोग के लिए असुरक्षित खजूर नष्ट कराए गए। इसी अभियान के तहत दो हजार किलो हल्दी, 20 हजार किलो सुपारी जब्त की गई, क्योंकि उसके खराब होने का संदेह था। सहारनपुर की एक खबर के अनुसार खाद्य विभाग ने रामपुर मनिहारान कस्बे में करीब साढ़े छह क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया।

गत दिनों ही भीलवाड़ा में एक कोल्ड स्टोरेज से बड़ी मात्रा में संदिग्ध मिलावटी मसाले जब्त किए गए। इनमें 23 सौ किलो लाल मिर्च पाउडर और 17 सौ किलो साबुत धनिया को मिलावटी होने के संदेह में जब्त किया गया। इसी माह गुजरात के साबरकांठा में डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया आदि का इस्तेमाल करके नकली दूध और छाछ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। यह फैक्ट्री पिछले पांच सालों से चल रही थी। बीते दिनों आंध्र के एक कस्बे में मिलावटी-जहरीला दूध पीने से पांच लोगों की मौत हो गई।

यदि बीते 15-20 दिनों की ही देश भर से आई ऐसी खबरों का संज्ञान लिया जाए तो उनका उल्लेख करने के लिए यह पूरा पेज या फिर समाचार पत्र भी कम पड़ सकता है। इन खबरों के आधार पर ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने की भूल नहीं की जानी चाहिए कि केवल त्योहारों पर ही नकली अथवा मिलावटी खाद्य पदार्थ बनने और बिकने लगते हैं। वास्तव में यह काम वर्ष भर बेरोक-टोक चलता है। किसी को इस नतीजे पर भी नहीं पहुंचना चाहिए कि जिन विभागों पर मिलावटी, नकली, घटिया खाद्य सामग्री पर निगाह रखने और उन्हें बनाने एवं बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, वे मिलावटखोरों के खिलाफ सदा सतर्क रहते हैं। सच यह है कि ऐसे विभाग केवल त्योहारों के समय ही सतर्क और सक्रिय दिखते हैं। यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि उनकी सतर्कता-सक्रियता उस मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री का एक हिस्सा ही पकड़ पाती है, जो बाजार में बिकने के लिए आ जाती है।

कल्पना करें कि अपने देश में कितने लोग टनों मिलावटी, नकली और सेहत के लिए हानिकारक खाद्य सामग्री उपभोग करने और ऐसा करके बीमार होने के लिए अभिशप्त हैं? मिलावटी एवं नकली खाद्य सामग्री के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों के दौरान ऐसी सूचना तो आती है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री के सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए, पर ऐसी खबर मुश्किल से ही आती है कि इन सैंपल के परिणाम क्या रहे?

यदि कभी ऐसी खबर आ भी जाती है तो यह पता चलना कठिन होता है कि मिलावटी या फिर नकली खाद्य सामग्री बनाने-बेचने वालों को सजा क्या मिली? ऐसी खबर मुश्किल से इसलिए आती है, क्योंकि ऐसे लोगों को सजा मिलने के मामले बहुत ही दुर्लभ हैं। केवल इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि अपने देश में नकली, मिलावटी या फिर घटिया किस्म की खाद्य सामग्री बनती और बिकती रहती है। चिंता की बात यह भी है कि दवाओं के मामले में भी यही स्थिति है। रह-रहकर ऐसी खबरें आती हैं कि अमुक-अमुक दवाओं के सैंपल फेल।

गत दिवस की एक खबर यह कहती है कि देश भर में निर्मित 215 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से जारी ड्रग अलर्ट के अनुसार इनमें से 71 दवाएं हिमाचल में बनी हैं। ये दवाएं मुख्य रूप से एलर्जी, अस्थमा, दर्द-बुखार की हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स और 16 कफ कोल्ड सीरप भी हैं। ऐसे ड्रग अलर्ट नए नहीं हैं और न ही वे यदाकदा जारी होते हैं। वे जारी ही होते रहते हैं, लेकिन नीति-नियंताओं का दोयम दर्जे की खाद्य वस्तुओं और दवाओं की ओर ध्यान तब जाता है, जब लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है।

आप उन खबरों से भी अनभिज्ञ नहीं हो सकते, जो यह बताती हैं कि नकली टूथपेस्ट, साबुन जैसे उत्पाद बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। बीते अगस्त में जयपुर में ऐसी ही एक फैक्ट्री में नामी टूथपेस्ट, क्रीम, साबुन आदि के साथ ब्रांडेड कंपनियों का नकली घी बन रहा था। इसी तरह दिल्ली में एक फैक्ट्री में नकली इनो बना रही फैक्ट्री पकड़ी गई थी। जिस देश में जानलेवा घटिया खाद्य सामग्री इतने बड़े पैमाने बन रही हो, वह आखिर विकसित कैसे बन सकता है? जहां ऐसे निकृष्ट कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं, वहां एआइ समिट में किसी यूनिवर्सिटी की ओर से चीनी रोबोटिक डाग को अपना बताकर पेश करने में किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।

अभियान

सूर्य की दिव्य ऊर्जा का रत्न माणिक्य: धारण करने से पहले अवश्य जान लें ये आवश्यक नियम

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, तेज, पिता, राजसत्ता, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना गया है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवनशक्ति का स्रोत है। जिस प्रकार सौरमंडल में सूर्य केंद्र में स्थित होकर सभी ग्रहों को प्रकाश और ऊर्जा देता है, उसी प्रकार मनुष्य की कुंडली में भी सूर्य व्यक्तित्व का केंद्र माना जाता है। जब जन्मकुंडली में सूर्य मजबूत होता है, तो व्यक्ति तेजस्वी, आत्मविश्वासी, निर्णयक्षम और सम्मानित होता है। लेकिन जब सूर्य कमजोर या पीड़ित हो, तो जीवन में अस्थिरता, आत्मविश्वास की कमी, पिता से मतभेद, स्वास्थ्य समस्याएँ और सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र सूर्य को सशक्त करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करने की सलाह देता है।

माणिक्य, जिसे अंग्रेज़ी में रूबी कहा जाता है, लाल रंग का अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली रत्न है। इसे 'रत्नों का राजा' भी कहा जाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे फलदीपिका और बृहत् जातक में भी सूर्य से संबंधित उपायों में माणिक्य धारण करने का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि यह रत्न सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर धारण करने वाले व्यक्ति के आभामंडल को तेजस्वी बना देता है। परंतु यह भी सत्य है कि जितना शक्तिशाली यह रत्न है, उतना ही संवेदनशील भी है। इसे धारण करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, या छठे, आठवें अथवा बारहवें भाव में अशुभ प्रभाव में हो, तब व्यक्ति को बार-बार असफलता, अपमान, आत्मग्लानि और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर भीड़ में बोलने से डरते हैं, निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और नेतृत्व की भूमिका से बचते हैं। माणिक्य धारण करने से सूर्य की ऊर्जा सक्रिय होती है और व्यक्ति के भीतर साहस, आत्मविश्वास और स्पष्टता का विकास होता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि माणिक्य पहनने के बाद उनकी वाणी में दृढ़ता आती है और वे अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने लगते हैं।

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार सूर्य पिता का कारक है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद या दूरी हो सकती है। माणिक्य धारण करने से इन संबंधों में सुधार आता है और पारिवारिक सम्मान में वृद्धि होती है। समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोग उसके विचारों को गंभीरता से लेने लगते हैं। यही कारण है कि राजनीति, प्रशासनिक सेवाओं, सेना, पुलिस या किसी भी उच्च पद की आकांक्षा रखने वाले लोगों को माणिक्य धारण करने की सलाह दी जाती है। यह रत्न नेतृत्व क्षमता को जागृत करने वाला माना जाता है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी माणिक्य को लाभकारी माना गया है। सूर्य हृदय, नेत्र और रक्त संचार का कारक है। जब सूर्य कमजोर होता है, तो हृदय संबंधी समस्याएँ, आँखों की कमजोरी या थकान की शिकायत हो सकती है। पारंपरिक मान्यता है कि माणिक्य धारण करने से आँखों की रोशनी में सुधार होता है, हृदय को बल मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हालांकि यह चिकित्सा का विकल्प नहीं है, परंतु ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे ऊर्जा संतुलन का साधन माना जाता है।

लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माणिक्य हर किसी को लाभ नहीं देता। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पहले से ही अत्यधिक प्रबल हो और क्रूर प्रभाव में हो, तो माणिक्य धारण करने से अहंकार, क्रोध, सिरदर्द, आँखों में जलन या रक्तचाप जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार यदि सूर्य अशुभ भाव का स्वामी होकर हानि दे रहा हो, तो बिना ज्योतिषीय परामर्श के इसे पहनना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए।

रत्नों की आपसी संगति भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सूर्य और शनि परस्पर शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए माणिक्य को नीलम के साथ पहनना वर्जित माना जाता है। इसी प्रकार सूर्य और शुक्र के संबंध भी मध्यम या प्रतिकूल हो सकते हैं, इसलिए हीरा के साथ इसे पहनने से बचना चाहिए। राहु और सूर्य की शत्रुता के कारण गोमेद के साथ भी माणिक्य धारण करने की सलाह नहीं दी जाती। ग्रहों की ऊर्जा आपस में टकराने पर व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता, निर्णय भ्रम या स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।

माणिक्य की शुद्धता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। रत्न प्राकृतिक, चमकदार और अंदर से स्वच्छ होना चाहिए। टूटा-फूटा, दरार वाला या कृत्रिम रत्न लाभ की बजाय हानि पहुँचा सकता है। वजन सामान्यतः 3 से 5 रत्ती या उससे अधिक ज्योतिषीय सलाह के अनुसार रखा जाता है। इसे सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाना श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये धातुएँ सूर्य से संबंधित हैं और उसकी ऊर्जा को प्रवाहित करने में सहायक होती हैं।

धारण करने की विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माणिक्य को रविवार के दिन, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में, सूर्योदय के समय धारण करना शुभ माना जाता है। धारण करने से पहले अंगूठी को गंगाजल, कच्चे दूध, शहद और शुद्ध जल से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद सूर्य मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर रत्न को ऊर्जित किया जाता है। सामान्यतः "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप किया जाता है। इसके पश्चात दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में अंगूठी धारण की जाती है। अनामिका उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसी में इसे पहनना सर्वोत्तम माना गया है।

माणिक्य धारण करने के बाद व्यक्ति को अपने व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने चाहिए। केवल रत्न पहन लेने से चमत्कार नहीं होता, बल्कि उसके साथ आत्मअनुशासन, सत्यनिष्ठा और परिश्रम भी आवश्यक है। सूर्य सत्य, कर्तव्य और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यदि व्यक्ति असत्य मार्ग अपनाए या अहंकार में डूब जाए, तो सूर्य की ऊर्जा विपरीत प्रभाव भी दे सकती है।

आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य आत्मा का कारक है। जब माणिक्य धारण किया जाता है, तो यह व्यक्ति के भीतर छिपी हुई आत्मशक्ति को जागृत करता है। व्यक्ति में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है और वह दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर विश्वास करने लगता है। यही कारण है कि इसे आत्मविश्वास का रत्न भी कहा जाता है।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि माणिक्य कोई जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा माध्यम है। इसका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली, ग्रह दशा और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि सही विधि, सही समय और उचित परामर्श के साथ इसे धारण किया जाए, तो यह जीवन में तेज, सम्मान और सफलता का मार्ग खोल सकता है। लेकिन यदि बिना विचार और बिना विश्लेषण के इसे पहन लिया जाए, तो लाभ की जगह हानि भी संभव है। इसलिए विवेक, ज्ञान और सही मार्गदर्शन के साथ ही सूर्य के इस दिव्य रत्न को धारण करें, ताकि यह आपके जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार कर सके।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को 6.97 करोड़ रुपए की सहायता मुख्यमंत्री ने डीबीटी से जमा कराई

▸▸ कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी तथा कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा की उपस्थिति

▸▸ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग द्वारा खरीफ एवं रबी मौसम के लिए प्रति एकड़ दो हजार रुपए की सहायता दी जाती है

▸▸ तीन ग्राम पंचायतों पर एक क्लस्टर अंतर्गत समग्र राज्य में 1015 क्लस्टर में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण-मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है

▸▸ प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों ने भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने का आत्मसंतोष प्राप्त हो; ऐसा कार्य किया है

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वस्थ जीवन के लिए बैक टू बेसिक मंत्र अपनाकर प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में अपनाने का आह्वान किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़े तथा अधिकाधिक किसान यह खेती अपनाएँ; इसके लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग द्वारा किसानों को प्रोत्साहक सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में राज्य में प्राकृतिक खेती से नए जुड़े 33 जिलों के 35,829 किसानों को गुरुवार को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत खरीफ मौसम हेतु एक एकड़ के लिए 2000 रुपए की सहायता का प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) से वितरण किया। कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी तथा कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा की उपस्थिति में गांधीनगर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कुल 6.97 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता सिंगल क्लिक से किसानों के बैंक खातों में जमा कराई।

राज्य में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से तीन ग्राम पंचायतों पर एक क्लस्टर; इस प्रकार बने कुल 1015 क्लस्टर में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहक सहायता प्रदान किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को स्वास्थ्यप्रद जीवन के लिए बैक टू बेसिक का मंत्र अपनाकर प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर अपनाने और ऐसी खेती से उत्पादित उत्पादों के व्यापक उपयोग का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रेरणा देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाकर भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने का आत्मसंतोष प्राप्त हो; ऐसा कार्य इन धरतीपुत्रों ने किया है।

श्री पटेल ने यह भी कहा कि राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने राज्य के किसानों को गाय आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने का जन आंदोलन चलाया है। वे गाँव-गाँव जाकर इसके लिए मार्गदर्शन भी दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती अब जब समय की मांग और हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य बन गई है, तब हम जितना जल्दी इस खेती की ओर मुड़ेंगे, उतना जल्दी फायदा मिलेगा।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि किसान देसी गाय आधारित तथा सरलता से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर रसायनमुक्त खेती करने लगें; इसके लिए भारत सरकार ने समग्र देश में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग शुरू कराया है। श्री वाघाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हमने राज्य में इस मिशन के तहत तीन ग्राम पंचायतों पर एक के हिसाब से कुल 1015 क्लस्टर कार्यरत किए हैं और शेष ग्राम पंचायतों में भी नॉन-मिशन अंतर्गत हर तीन ग्राम पंचायत पर एक के हिसाब से कुल 3875 क्लस्टर का गठन किया जाएगा। इस प्रकार; कुल लगभग 4890 क्लस्टर के गठन से प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने की योजना है।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं; किसानों को प्राकृतिक खेती की प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 7100 मॉडल फार्म का निर्माण हुआ है। इस वर्ष के बजट में भी प्राकृतिक खेती की विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकार ने 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री आर. सी. मीणा, गुजरात एग्रो के प्रबंध निदेशक श्री विजय खराडी, कृषि निदेशक श्री राजेन्द्रसिंह राजपूत, गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के श्री पटेल, अधिकारी तथा लाभार्थी ग्रामीण किसान उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा वड़ोदरा मंडल पर "संवाद" का सफल आयोजन

जीएनएस)। दिनांक 26.02.2026 को पश्चिम रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा वडोदरा मंडल पर एक "संवाद" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री तरुण जैन, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम रेलवे ने की एवं इस अवसर पर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (मालभाड़ा) श्री जेरिन जी. आनंद तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वडोदरा श्री नरेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुंबई, वडोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट एवं भावनगर मंडलों से लगभग 50 से अधिक फील्ड कर्मचारियों ने भाग लिया। संवाद के दौरान वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों ने अपने दैनिक कार्य में आने वाली समस्याओं को प्रमुखता से पटल पर रखा तथा उनके व्यावहारिक समाधान भी सुझाए। इस संवाद में भविष्य में पार्सल और माल राजस्व में वृद्धि हेतु नए सुझावों पर भी गहन चर्चा की गई। यह पहल फील्ड कर्मचारी एवं उच्च प्रबंधन के मध्य एक समन्वय स्थापित करने में एक कड़ी का कार्य करेगी एवं रेल राजस्व की वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए वातानुकूलित लोकल सेवाओं में वृद्धि

जीएनएस)। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम रेलवे पर वातानुकूलित (एसी) लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यात्रियों की बढ़ती लोकप्रियता और मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे मुंबई उपनगरीय खंड में वातानुकूलित लोकल सेवाओं की संख्या निरंतर बढ़ा रही है। वर्तमान में पश्चिम रेलवे द्वारा अपने उपनगरीय नेटवर्क पर सोमवार से शुक्रवार 133 एसी लोकल सेवाएं संचालित की जा रही है। वहीं शनिवार और रविवार को 106 एसी लोकल सेवाएं चलाई जा रही हैं, जिससे सप्ताहांत में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा और आराम मिल रहा है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस वर्ष कई नई लोकल सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनमें एसी सेवाएं भी शामिल हैं। जनवरी माह में 12 एसी लोकल सेवाएं शुरू की गईं तथा फरवरी में 12 और सेवाएं जोड़ी गईं। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे पर एसी सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर 133 हो गई है। एसी सेवाओं की बढ़ी हुई संख्या से यात्रियों को सप्ताहांत में भी सुविधाजनक, आरामदायक और वातानुकूलित यात्रा का अनुभव मिल रहा है। श्री विनीत ने आगे बताया कि एसी लोकल ट्रेनें बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करती हैं और उपनगरीय नेटवर्क के विभिन्न वर्गों के यात्रियों से इन्हें लगातार सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। सप्ताहांत पर अतिरिक्त एसी सेवाओं की उपलब्धता से विशेष रूप से उन यात्रियों को लाभ हुआ है जो कार्यालय, अवकाश या अन्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए यात्रा करते हैं। साथ ही, इससे आगामी ग्रीष्म ऋतु में भी यह यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम रेलवे सुरक्षित, कुशल और यात्री-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसी लोकल सेवाओं की बढ़ी हुई उपलब्धता दैनिक यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करने और मुंबई की जीवनरेखा को और सुदृढ़ बनाने के इसके निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

साणंद जीआईडीसी में प्रीमियम होटल बनाने के लिए प्लॉट की नीलामी पूर्ण, लगभग 5 एकड़ भूमि डेवलपर को आवंटित

▸▸ चार वर्ष में निर्माण कार्य का प्रावधान, साणंद औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि

▸▸ गुजरात में सेमीकंडक्टर क्षेत्र तथा औद्योगिक इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील

जीएनएस)। गांधीनगर : साणंद औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत नेशनल तथा मल्टीनेशनल कंपनियों की सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से होटल निर्माण के लिए प्लॉट की नीलामी पूर्ण की गई है। साणंद-2 औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 20168.54 वर्ग मीटर (अनुमानित 5 एकड़) प्लॉट विशेष रूप से प्रीमियम होटल निर्माण के लिए रिजर्व किया गया था, जिसकी नीलामी गत 22 दिसंबर, 2025 को पूर्ण की गई है।

इस ई-नीलामी में अधिकतम बिड के साथ

डेवलपर को नियमों के अनुसार प्लॉट का आवंटन किया गया है। 3 से 5 स्टार होटल के निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए कंपनी को चार वर्ष का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है। इस होटल के अतिरिक्त; साणंद औद्योगिक क्षेत्र के 3 किलोमीटर निकट एक फाइव स्टार होटल के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। आगामी 28 फरवरी, 2026 को साणंद औद्योगिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ कराएंगे। इस प्रकार की विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों की उपस्थिति होने के कारण यहाँ की यात्रा पर आने वाले डेलीगेट्स तथा कर्मचारियों के रहने के लिए यह होटल सुविधा महत्वपूर्ण सिद्ध बनेगी। राज्य में उद्योगों की जरूरत के अनुरूप सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सघन प्रयास चल रहे हैं।

साणंद औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सुव्यवस्थित कनेक्टिविटी होने के कारण उद्योगों का निरंतर विकास हो रहा है। हाल में साणंद औद्योगिक क्षेत्र में 1150 औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। साणंद में महिलाओं के लिए समर्पित महिला औद्योगिक पार्क बनाया गया है, जिसके द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियाँ बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विजन को चरितार्थ किया है।

क्रूड ऑयल वायदा 119 रुपये फिसला: सोना वायदा में 1983 रुपये और चांदी वायदा में 9449 रुपये की गिरावट

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 24367.08 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 298684.89 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 20046.33 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39750 पॉइंट के स्तर पर

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 323052.21 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 24367.08 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 298684.89 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 39750 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1793.66 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 20046.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 160530 रुपये के भाव पर खूलकर, 160858 रुपये के दिन के उच्च और 159106 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 161145 रुपये के पिछले बंद के सामने 1983 रुपये या 1.23 फीसदी लुढ़ककर 159162 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 1210 रुपये या 0.93 फीसदी घटकर 129571 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 136 रुपये या 0.83 फीसदी घटकर 16324 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मार्च वायदा 158427 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 158510 रुपये और नीचे में 156870 रुपये पर पहुंचकर, 1949 रुपये या 1.23 फीसदी घटकर 156969 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 160998 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 161309 रुपये और नीचे में 159769 रुपये पर पहुंचकर, 161517 रुपये के पिछले बंद के सामने 1668 रुपये या 1.03 फीसदी घटकर 159849 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 264300 रुपये के भाव पर खूलकर, 266800 रुपये के दिन के उच्च और 255172 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 268316 रुपये के पिछले बंद के सामने 9449 रुपये या 3.52 फीसदी की गिरावट के साथ 258867 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 11655 रुपये या 4.14 फीसदी औंधकर 269750 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 11509 रुपये या 4.09 फीसदी गिरकर 269899 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 2539.92 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 8.85 रुपये या 0.73 फीसदी घटकर 1202.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 2.6 रुपये या 0.79 फीसदी की गिरावट के साथ 325.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 1.8 रुपये या 0.57 फीसदी औंधकर 311.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 1.05 रुपये या 0.55 फीसदी घटकर 188.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1674.09 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 5978 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5983 रुपये और नीचे में 5856 रुपये पर पहुंचकर, 119 रुपये या 1.99 फीसदी घटकर 5870 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 116 रुपये या 1.94 फीसदी लुढ़ककर 5871 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 261.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 262.2 रुपये के दिन के उच्च और 254.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 264.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 9.5 रुपये या 3.59 फीसदी की गिरावट के साथ 255 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 9.6 रुपये या 3.63 फीसदी गिरकर 255.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा 961.1 रुपये पर खूलकर, 3.7 रुपये या 0.39 फीसदी घटकर 957 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 9823.35 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 10222.98 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2143.96 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 150.28 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 15.79 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 226.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 683.68 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 965.15 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.00 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9385 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 74691 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 29553 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 366823 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 50917 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9724 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 17056 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 58900 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17751 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 30183 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 39750 पॉइंट पर खूलकर, 39750 के उच्च और 39750 के नीचले स्तर को छूकर, 430 पॉइंट घटकर 39750 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 49.2 रुपये की गिरावट के साथ 271.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.7 रुपये की गिरावट के साथ 14.85 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1264 रुपये की गिरावट के साथ 680 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5438 रुपये की गिरावट के साथ 11856.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.79 रुपये की गिरावट के साथ 41.01 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 86 पैसे की नरमी के साथ 3.64 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 5900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 64 रुपये की बढ़त के साथ 340.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.5 रुपये की बढ़त के साथ 20.4 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 4 रुपये की गिरावट के साथ 44 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3130.5 रुपये की बढ़त के साथ 19000 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.21 रुपये की बढ़त के साथ 37.24 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 39 पैसे के सुधार के साथ 3.49 रुपये हुआ।

साणंद में माइक्रोन का मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट एआई टेक्नोलॉजी के भविष्य को सशक्त बनाएगा

▸▸ साणंद के प्लांट में बनेंगे एसएसडी तथा रैम प्रकार के स्टोरेज एवं मेमोरी उपकरण

▸▸ 2000 लोगों की टीम कार्यरत, आगामी समय में 5 हजार लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, दिव्यांग नागरिकों के लिए भी नौकरी के अवसर उपलब्ध

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में शुरू हुई क्रांति में गुजरात नेतृत्व की भूमिका में

जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भगीरथ प्रयासों से भारत अब नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में भी डंका बजाने को तैयार है। आगामी 28 फरवरी, 2026 को गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक एटीएमपी (असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग) प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लि. द्वारा 22,516 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और गुजरात में माइक्रोन की एटीएमपी सुविधा के शुरू होने से भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नई क्रांति का शुभारंभ होगा।

माइक्रोन के साणंद प्लांट में 2000 लोगों की टीम कार्यरत, दिव्यांग नागरिकों के लिए भी अवसर

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात समग्र देश में नेतृत्व की भूमिका में है और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सघन प्रयासों से साणंद में माइक्रोन का प्लांट निर्धारित समयसीमा में कार्यरत होने जा रहा है। यह प्लांट एक एटीएमपी सुविधा है; जिसमें एसएसडी (सॉलिड स्टेट ड्राइव-हार्ड डिस्क प्रकार के स्टोरेज के लिए आधुनिक उपकरण) तथा रैम प्रकार के डीआरएएम एवं एनएएनडी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। साणंद प्लांट में हाल में 2000 लोगों की टीम कार्यरत है, जिसमें आगामी समय में 5 हजार लोगों को सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। माइक्रोन टीम के कथनानुसार यहाँ दिव्यांग नागरिक भी ऑपरेटर तथा टेक्निशियन के रूप में कार्य करते हैं और कौशल से सज्ज सभी तरह के नागरिकों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं।

साणंद प्लांट में तैयार होने वाले उत्पाद एआई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी

एटीएमपी प्लांट में किस प्रकार कार्य होता है ?

एटीएमपी प्लांट का कार्य वेफर चिप्स से शुरू होता है। सबसे पहले हम ये समझें कि एटीएमपी सविधा तक पहुँचने से पहले ये चिप्स किस तरह बनती हैं। सेमीकंडक्टर चिप बनाने की प्रक्रिया रेत (सैंड) से शुरू होती है। सबसे पहले रेत से प्योर सिलिकॉन को अलग किया जाता है। इस सिलिकॉन को पिघलाकर उसका सिलेंडर बनाया जाता है, जिसे इनगोट कहा जाता है। इस सिलेंडर को काटकर उसमें से सूक्ष्म प्लेट्स बनाई जाती हैं, जिसे वेफर्स कहा जाता है। इसके बाद फैब्रिकेशन प्लांट में इन वेफर्स पर इलेक्ट्रिक पैटर्न प्रिंट किया जाता है और कई आवरण (लेयर्स) उस पर चढ़ाए जाते हैं। इन आवरणों को फोटोलिथोग्राफी द्वारा उचित ढंग से नियोजित करने से वेफर्स पर ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। इसके द्वारा वेफर्स पर मेमोरी बनती है और इन वेफर्स में मेमोरी चिप लगाई जाती है। इसके बाद वेफर्स के छोटे चौकोर टुकड़े किए जाते हैं, जिसे चिप कहा जाता है।

यह चिप इसके बाद एटीएमपी प्लांट में पहुँचती है। यहाँ पहले उसे असेम्बल किया जाता है। इसके बाद टेस्टिंग के चरण में उसकी स्पीड, मेमोरी तथा कार्य की संपूर्ण टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद उसकी विवरणबद्ध मार्किंग कर अंत में उसकी पैकेजिंग की जाती है, जिससे वह मार्केट में पहुँच सके। साणंद प्लांट में विश्वभर के मार्केट के अनुरूप इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज, मॉड्यूल तथा सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए माइक्रोन की वैश्विक फैक्ट्रियों में निर्मित अत्याधुनिक डीआरएएम तथा एनएनडी वेफर्स मिलाकर उन्हें फाइनल मेमोरी उत्पादों में परिवर्तित किया जाएगा। ये उत्पाद एआई क्षेत्र में मेमोरी तथा स्टोरेज की बढ़ रही मांग को पूर्ण करने में सहायक होंगे।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष तथा सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा ने कहा कि वर्तमान टेक्नोलॉजी में; विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में मेमोरी एवं स्टोरेज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत मेमोरी तथा स्टोरेज सपोर्ट के बिना एआई प्रणालियाँ उचित ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं। जैसे-जैसे एआई अधिक तेज एवं रियल-टाइम रिस्पॉन्स देना शुरू करता है, वैसे-वैसे उसे अधिक तथा और अत्याधुनिक मेमोरी की जरूरत पड़ती है।

लग्जमबर्ग ग्रैंड डची के वित्त मंत्री श्री गिलिस रोथ तथा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले गुजरात को ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन ग्रोथ में अग्रसरता के लिए लग्जमबर्ग की विशेषज्ञता के लाभ के लिए परामर्श किया
- लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपसी सहयोग को लेकर आयोजित बैठक में चर्चा की गई
- गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सेक्टर में निवेश के लिए लग्जमबर्ग की उत्सुकता

जीएनएस)। गांधीनगर : लग्जमबर्ग ग्रैंड डची के वित्त मंत्री श्री गिलिस रोथ तथा प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। लग्जमबर्ग की 115 बैंकों के साथ एसेट मैनेजमेंट में 8 ट्रिलियन यूरो का निवेश और लगभग 80 देशों में इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में उपस्थिति है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत-गुजरात के साथ वित्तीय संबंध विस्तृत करने की उत्सुकता दर्शाई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक में हुई चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला राज्य है। इतना ही नहीं; गुजरात ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फाइनेंसिंग तथा ग्रीन ग्रोथ में लीड लेने के लिए सज्ज है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने इस आशय पर विचार-विमर्श किया कि लग्जमबर्ग की ग्रीन बॉण्ड तथा ग्रीन फाइनेंसिंग क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ गुजरात को मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रिन्यूएबल-ग्रीन एनर्जी तथा मिशन लाइफ से पर्यावरणानुकूल जीवन शैली के साथ दिए गए ग्रीन ग्रोथ के विचार को म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड्स तथा लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से साकार किया जा सके; इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से आपसी सहयोग की संभावनाएँ तलाशने का अनुरोध किया।

लग्जमबर्ग ग्रैंड डची के वित्त मंत्री श्री गिलिस रोथ ने कहा कि गिफ्ट सिटी में आईएफएससीए तथा लग्जमबर्ग के सीएसएसएफ के बीच हुए एमओयू से भारत एवं लग्जमबर्ग का वित्तीय सहयोग अधिक मजबूत हुआ है और गुजरात की ग्लोबल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। श्री गिलिस रोथ ने गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सेक्टर में अधिक निवेशों के लिए लग्जमबर्ग की उत्सुकता दर्शाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने लग्जमबर्ग के प्रतिनिधिमंडल को आगामी जनवरी-2027 में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट तथा अप्रैल-2026 व जून-2026 में आयोजित होने वाली दक्षिण एवं मध्य गुजरात की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया।

श्री गिलिस रोथ ने मुख्यमंत्री तथा गुजरात सरकार के प्रतिनिधिमंडल को लग्जमबर्ग ग्रैंड डची की यात्रा पर आने का भावपूर्ण आमंत्रण दिया।

इस शिष्टाचार बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप तथा मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे भी सहभागी हुए।

बजट अपडेट : महिला एवं बाल कल्याण विभाग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सुपोषित भारत' विजन को वेग देने के लिए महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में 7,690 करोड़ रुपए का प्रावधान

जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सुपोषित भारत' विजन को और वेग देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में 7,690 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील की अध्यक्षता में गांधीनगर में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ।

आँगनबाड़ी क्षेत्र में ढाँचागत सुधार के लिए राज्य में 2,000 नए आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 360 करोड़ रुपए का प्रावधान।

आँगनबाड़ी केन्द्र 'चाइल्ड फ्रेंड्ली' कॉन्सेप्ट पर बनेंगे; जिनमें मॉड्यूलर फर्नीचर, आरओ मशीन, एलईडी टीवी स्क्रीन तथा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ।

आदिजाति क्षेत्रों के 53 घटकों में दूध संजीवनी योजना का विस्तार किया जाएगा। दूध में फैट का प्रमाण 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत (पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नर्मदा, दाहोद व डांग में) करने के लिए 38.64 करोड़ रुपए का प्रावधान।

कम वजन वाले बच्चों के सुधार के लिए हेल्थ चेकअप तथा होम विजिट के पोषण संगम कार्यक्रमों के लिए 16 करोड़ रुपए।

आँगनबाड़ियों तथा पोषण स्तर की सघन मॉनिटरिंग करने के लिए पोषण प्रगति तथा निरीक्षण केन्द्र बनाए जाएंगे।

आँगनबाड़ी के बच्चों की उपस्थिति एवं मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम हेतु एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम विकसित किया गया है।

राशन की चोरी रोकने तथा डिजिटल ट्रैकिंग संभव बनाने के लिए पूरक पोषण योजना-टीएचआर की पैकेजिंग पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा।

किशोरियों में नेतृत्व के गुण विकसित करने तथा पंचायतीराज एवं बाल अधिकारों के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से बालिका पंचायत योजना अंतर्गत 1.03 करोड़ रुपए का आवंटन।

तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाली बालिका पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा।

इस संवाददाता सम्मेलन में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव श्री राकेश शंकर सहित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना

'आत्मा गांव की, सुविधा शहर की' आधुनिक तथा आदर्श गांवों की दिशा में पहल

जीएनएस)। गांधीनगर : पीने के पानी, कूड़ा प्रबंधन तथा गंदे पानी के उपचार जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास। मुख्य तथा आंतरिक मार्गों के निर्माण द्वारा सशक्त परिवहन व्यवस्था। ई-लाइब्रेरी, खेल के मैदान तथा तालाब के आसपास वॉक-वे जैसी आधुनिक सुविधाओं का समावेश। स्ट्रीट लाइट तथा सार्वजनिक शौचालय जैसी नागरिक सुविधाओं से गांवों को सुसज्जित बनाने का उद्देश्य। चयनित गांवों में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का संतृप्ति स्तर सुनिश्चित करने का लक्ष्य। वर्ष 2026-27 के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक और सुविधासंपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

अटल वाडी योजना – ग्रामीण स्तर पर सामूहिक सशक्तिकरण का नया केन्द्र

वर्ष 2026-27 के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान

गांधीनगर : ग्रामीण स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए सुविधायुक्त स्थान उपलब्ध कराने का उद्देश्य।

गांव की वाडी के रूप में विकसित किया जाने वाला यह स्थान ग्रामीणों के लिए एकता, संवाद और संस्कृति का केंद्र बनेगा।

ग्रामीण स्तर पर सामूहिक गतिविधियों के लिए सशक्त आधारभूत सुविधा विकसित करने का प्रयास।

ग्रामीण स्तर पर सामूहिक आधारभूत सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।

बजट अपडेट – ऊर्जा विभाग

गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन अंतर्गत महानगर पालिका तथा नगर पालिका क्षेत्रों में ओवरहेड विद्युत नेटवर्क को भूमिगत केबल नेटवर्क में रूपांतरित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का नया प्रावधान

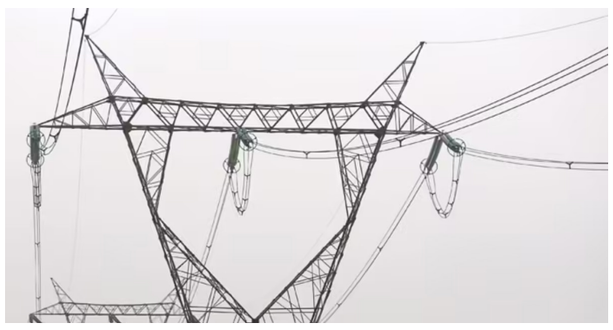

जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य के विकास एवं नागरिकों की बढ़ती विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए निर्बाध्य, सुरक्षित तथा उच्च गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

इस पहल से राज्य के नागरिकों तथा अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, जलापूर्ति, बस अड्डों, पुलिस थानों आदि जैसी आवश्यक सेवाओं को विक्षेप रहित तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति निर्बाध्य रूप से मिलेगी।

इस पहल से पावर विक्षेपों में कमी आएगी, शहरी घने क्षेत्रों में अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी इस मिशन से खुले वायरों से होने वाली दुर्घटनाओं के निवारण में भी काफी मदद मिलेगी। यह पहल गुजरात को अधिक सुव्यवस्थित तथा स्मार्ट शहरी राज्य के रूप में आगे बढ़ाएगी।

राज्य को कॉमनवेल्थ तथा ओलंपिक रेडी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध ढंग से सभी महानगर पालिका तथा नगर पालिका क्षेत्रों को वायर फ्री सिटी में रूपांतरित किया जाएगा।

राज्य के यात्राधाम क्षेत्रों को ग्रीन तथा विद्युत सुरक्षित जोन में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान

जीएनएस)। गांधीनगर : यात्राधामों में निरंतर तथा गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति बनी रहे, विद्युत सुरक्षा का स्तर बढ़े और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिले; इस उद्देश्य से विद्युत वितरण ढाँचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। रूफटॉप सोलर सिस्टम का प्रचार तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी

पर्यटन तथा मंदिर के कामकाज और त्योहारों के दौरान विश्वसनीय एवं निरंतर विद्युत आपूर्ति बनी रहेगी।

अंडरग्राउंड नेटवर्क, व्यवस्थित वितरण प्रणाली और आधुनिक सुविधाओं के जरिये यात्राधामों के सौंदर्य में वृद्धि

सरकारी भवनों तथा लोकल ऑथोरिटी के भवनों पर अधिकतम् 50 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम इन्स्टॉलेशन के लिए राज्य की सोलर सब्सिडी सहायता

यह योजना विद्युत वितरण नवीनीकरण के जरिये नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय तथा आधुनिक बनाने के लिए है, जिसमें केबलिंग, ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड तथा मेंटनेंस पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रारंभिक चरण में द्वारका, सोमनाथ, अंबाजी तथा पालीताणा यात्राधामों के क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर ग्रीन एवं विद्युत सुरक्षित जोन में विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

यात्रियों की विद्युत सुरक्षा तथा यात्राधामों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य होगा।

राज्य के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में ओवरहेड वितरण नेटवर्क को आधुनिक ऊँचाई वाले केबल नेटवर्क में रूपांतरित करने के लिए 100 करोड़ रुपए

गांधीनगर : गुजरात की सीमा अत्यंत संवेदनशील है और वहाँ हमारे जवानों को निरंतर बिजली देना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है।

कच्छ की सीमा पर जलवायु के दुर्गम प्रभावों के कारण ओवरहेड विद्युत वायर तथा पोल कट जाते/ठप हो जाते हैं और चक्रवात की स्थिति में विद्युत वायर तथा पोल गिर जाने के कारण बीएसएफ के जवानों को विद्युत आपूर्ति विक्षेप की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए संवेदनशील सीमा पर स्थित बॉर्डर आउट पोस्ट्स (बीओपी) पर ओवरहेड विद्युत वायरों के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी वाले एलिवेटेड केबल उपयोग में लिए जाएंगे और बीएसएफ को निरंतरतापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जाएगी।

बजट अपडेट- पंचायत

मुख्यमंत्री निर्मल ग्राम योजना – स्वच्छता और स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार

- वर्तमान स्थिति में 12 जिलों की 21 तहसीलों के 667 गांवों में यह योजना कार्यरत है
- 650 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान

गांधीनगर : ग्राम पंचायत द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए एजेंसी नियुक्त कर एकत्रित कचरे को निर्धारित डंपिंग साइट पर डाला जाएगा।

संबंधित तहसील द्वारा एजेंसी नियुक्त कर इस प्रकार एकत्रित कचरे को प्रत्येक गांव से एकत्र कर निकटतम नगर पालिका/महानगर पालिका के प्रोसेसिंग यूनिट (डंपिंग साइट) तक पहुंचाने का कामकाज किया जाएगा।

अर्बन अथोरिटी; आरयूडीए, जीयूडीए, वीयूडीए में भी यह योजना कार्यरत है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता स्तर को ऊंचा उठाना और स्वास्थ्य में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध परिसंपत्तियों और वाहनों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

आधुनिकता की पटरी पर भीलड़ी: पुनर्विकास का 90% कार्य पूर्ण,अमृत भारत स्टेशन योजना से बदल रही स्टेशन की सूरत, लिफ्ट और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं से होगा लैस

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भीलड़ी रेलवे स्टेशन का अमृत स्टेशन योजना के तहत लगभग 11.00 करोड़ की अनुमानित लागत से व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है। इस परियोजना का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। आधुनिक स्टेशन भवनः स्टेशन पर 18,223 वर्गफीट क्षेत्र में एक नया आधुनिक भवन बनाया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक बुकिंग कार्यालय और वातानुकूलित व गैर-वातानुकूलित प्रतीक्षालय की सुविधा होगी। बेहतर कनेक्टिविटी और एप्रोचः यात्रियों की सुविधा के लिए 39,288 वर्गफीट लंबी एप्रोच रोड का सुधार व चौड़ीकरण किया गया है और 29,105 वर्गफीट क्षेत्र में सर्कुलेटिंग एरिया व पार्किंग का विकास किया जा चुका है। उन्नत प्रतीक्षालय और शौचालयः स्टेशन पर 1,582 वर्गफीट के प्रतीक्षालय का उन्नयन किया गया है और कुल 5 शौचालय ब्लॉकों में से 4 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

लिफ्ट और यात्री-अनुकूल सुविधाएंः सभी प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है तथा दिव्यांगजनों के लिए विशेष रैंप, पोर्च, सुगम प्रवेश/निकास द्वार और पृथक शौचालय व पार्किंग विकसित की गई है तथा यात्रियों को बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में बेंचे भी लगाई गई है। पार्किंग और सौंदर्यीकरणः परिसर में चार पहिया, दो पहिया और ऑटो-रिक्शा के लिए अलग-अलग पार्किंग, प्लेटफॉर्म शेल्टर का विस्तार, हरित क्षेत्र का विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य अंतिम चरण में है।

भविष्य की क्षमता का विस्तारः वर्तमान में भीलड़ी स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 12,00 यात्री आवाजाही करते है तथा 40 से अधिक ट्रेनों का ठहराव एवं आगमन-प्रस्थान इस स्टेशन से होता है। इस स्टेशन को भविष्य में 25,000 यात्रियों की दैनिक आवाजाही के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। आर्थिक और सामरिक महत्वः यह स्टेशन मालगाड़ियों और डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसका पुनर्विकास स्थानीय समुदाय को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

सुरक्षित एवं आधुनिक यात्रा अनुभवः इस पुनर्विकास के पूर्ण होने के बाद भीलड़ी स्टेशन यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करेगा, जो पश्चिम रेलवे की आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत और कनाडाः कूटनीतिक तनाव से रणनीतिक पुनर्संतुलन की ओर

जीएनएस)। प्रस्तावित भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत–कनाडा द्विपक्षीय संबंध एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। लगभग दो वर्षों तक चले कूटनीतिक तनाव के बाद, नई दिल्ली और ओटावा दोनों ही अब संबंधों को स्थिर करने और राजनीतिक विश्वास की आंशिक बहाली की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

भारत और कनाडा के संबंध ऐतिहासिक रूप से कॉमनवेल्थ विरासत, विस्तारित व्यापारिक संपर्कों और कनाडा में बसे सशक्त भारतीय प्रवासी समुदाय पर आधारित रहे हैं। लगभग 18 लाख भारतीय मूल के नागरिक दोनों समाजों के बीच एक स्थायी सेतु का कार्य करते हैं।

फिर भी, हाल के वर्षों की घटनाओं ने इस मजबूत दिखने वाली संरचना के भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर किया है।

कूटनीतिक तनाव का चरण

पहला स्पष्ट राजनीतिक विचलन 2020–21 के दौरान भारत में हुए किसान आंदोलनों के समय सामने आया, जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से इन आंदोलनों पर चिंता व्यक्त की। भारत सरकार ने इन टिप्पणियों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा, जिससे द्विपक्षीय संवाद में असहजता उत्पन्न हुई।

इसके बाद 2022–23 के दौरान तनाव और गहराया, जब भारत ने कनाडा में भारत-विरोधी गतिविधियों, विशेषकर खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा भारतीय राजनयिक मिशनों को दी गई धमकियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की।

सितंबर 2023 में यह संकट उस समय चरम पर पहुँच गया, जब कनाडाई संसद में यह आरोप लगाया गया कि भारत सरकार से जुड़े तत्व एक कनाडाई नागरिक, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। भारत ने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए सख्ती से खारिज किया।

इस घटनाक्रम का प्रभाव गहरा रहा। दोनों देशों ने अपने राजनयिक कर्मियों की संख्या घटाई और कुछ समय तक उच्चायुक्त स्तर पर प्रतिनिधित्व भी रिक्त रहा। यह प्रकरण केवल एक कूटनीति मतभेद नहीं था, बल्कि आपसी विश्वास में आई गंभीर दरार को दर्शाता था। जब संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे घरेलू राजनीति से टकराते हैं, तो कूटनीतिक संवाद का दायरा स्वतः संकुचित हो जाता है।

रणनीतिक पुनर्संतुलन की दिशा में

कनाडा की घरेलू राजनीति में आए बदलावों के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक विदेश नीति संकेत दिए। कनाडा की जी7 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करना संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक प्रारंभिक संकेत के रूप में देखा गया। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर एवं कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की

वार्ता एवं दोनों देशों द्वारा उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी सामान्यीकरण की प्रक्रिया को दर्शाती है।

हालाँकि, यह पुनर्संतुलन एकतरफा नहीं है। भारत के लिए कनाडा के साथ संवाद उसकी व्यापक विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा संवेदनशीलताओं और आर्थिक–प्रौद्योगिकीय सहयोग के बीच संतुलन साधना प्रमुख है।

भारत की विदेश नीति आज भी रणनीतिक स्वायत्तता और मुद्दा-आधारित साझेदारियों पर आधारित है, न कि कठोर गुटबद्धताओं पर। इस दृष्टि से भारत–कनाडा संबंधों में यह पुनर्संयोजन भावनात्मक सामंजस्य नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकताओं का परिणाम है।

संबंधों के संरचनात्मक आधार

राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत–कनाडा संबंधों की संरचनात्मक तर्कशीलता बनी हुई है।

* व्यापार और आर्थिक अंतर्संबंध

वर्ष 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। भारत फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियर्ड उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि कनाडा दालें, उर्वरक और ऊर्जा-संबंधी उपकरण उपलब्ध कराता है। विशेष रूप से कनाडाई दालों का भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है।

* शिक्षा और प्रवासी आयाम

कनाडा भारतीय छात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है। 2025 तक लगभग 96,000 भारतीय छात्र वहाँ अध्ययनरत थे। यह शैक्षिक आवागमन न केवल सामाजिक संपर्क बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक और ज्ञान-आधारित संबंधों को भी सुदृढ़ करता है।

* महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा

ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में कनाडा के पास उपलब्ध लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, पोटाश और दुर्लभ मृदा तत्व भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं।

विद्युत गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर निर्माण और उन्नत उद्योगों में भारत की आकांक्षाओं के लिए विविध और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाएँ अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी हैं।

*वृहत्तर भू-राजनीतिक संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापारिक और राजनीतिक तनावों के चलते कनाडा ने अपने आर्थिक साझेदारों में विविधता लाने की आवश्यकता को महसूस किया है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री कार्नी ने एकतरफा शुल्क व्यवस्थाओं और आपूर्ति श्रृंखला अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की।

कार्नी की हालिया चीन यात्रा ने भी कनाडा–अमेरिका संबंधों में निहित तनावों को और स्पष्ट किया, जिससे ओटावा के लिए रणनीतिक संतुलन की आवश्यकता और प्रबल हुई।

इसी व्यापक संदर्भ में भारत–कनाडा संवाद को देखा जाना चाहिए। भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका ने द्विपक्षीय समीकरण को नया स्वरूप दिया है। आज यह संवाद भारत की सुदृढ़ वैश्विक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, न कि किसी प्रकार की कूटनीतिक अनिवार्यता को।

* एक बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभावशाली मध्य शक्तियों के रूप में भारत और कनाडा के हित निम्न क्षेत्रों में अभिसरितः

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता

क्लीन एनर्जी , हाइड्रोजन और परमाणु सहयोग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं डिजिटल गवर्नेंस

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान में साझेदारियां

स्थिर सप्लाई चैन

* रणनीतिक परिपक्वता के माध्यम से स्थिरता

फरवरी 2026 में दोनों देशों द्वारा सुरक्षा और कानून-प्रवर्तन संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति पर सहमति इस बात का संकेत है कि संबंधों को संस्थागत आधार पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुंबई और नई दिल्ली यात्रा टकराव से सावधान पुनर्संतुलन की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है। किंतु दीर्घकालिक सामान्यीकरण तभी संभव होगा जब सुरक्षा चिंताओं का समाधान करते हुए आर्थिक और तकनीकी सहयोग को राजनीतिक अस्थिरताओं से संरक्षित किया जा सके।

यह सहभागिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कूटनीतिक दृष्टि को भी प्रतिबिंबित करती है, जो व्यवहारिक सहभागिता (pragmatic engagement) पर आधारित है तथा भारत के सामरिक हितों के अनुरूप साझेदारियों के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है।

विखंडित वैश्विक व्यवस्था में भारत और कनाडा आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, आर्थिक रिज़िलीअन्स और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में साझा हित रखते हैं। इन संरचनात्मक समानताओं को स्थायी राजनीतिक विश्वास में परिवर्तित करना ही दोनों देशों के संबंधों की भावी दिशा तय करेगा।

मोबाइल का दुरुपयोग प्रेम और विश्वास के लिए खतरा पैदा करता है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन एक आवश्यकता बन गए हैं, यहाँ तक कि इनका उपयोग पहले से कहीं अधिक हो रहा है, क्योंकि अब मोबाइल फोन के कैमरे से बेहतरीन तस्वीरें और वीडियो लिए जा सकते हैं। इसी तरह, इनका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जा सकता है। मोबाइल फोन स्वयं कोई अपराध नहीं करते, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में इनका उपयोग बढ़ गया है। शादी से पहले प्रेमी जोड़े अपने निजी पलों के वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने की हिम्मत करते हैं। वे प्रेमी जोड़े निजी पलों का आनंद लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने का सुख जानते हैं। लेकिन ऐसा करके वे एक बड़ा और गलत जोखिम उठाते हैं।

शून्य त्रुटि एजेंसी

मान लीजिए कि प्रेमिका को वीडियो बनाने में आनंद आता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह इसके लिए क्यों राजी हुई। यदि कोई अपने शरीर को दिखाने में संकोच करता है, तो प्रेमिका द्वारा वीडियो बनाने के लिए अपने शरीर को दिखाने पर प्रेम का महत्व अकल्पनीय रूप से बढ़ जाता है। क्या किसी को यह नहीं लगता कि प्रेमिका इस वीडियो का दुरुपयोग भी कर सकती है?

और अखबारों में ऐसी कितनी घटनाएं

छपी हैं? फिर प्रेमी अपने साथी को ऐसे वीडियो डाउनलोड करने की इजाज़त क्यों देता है, जबकि उसे आनंद से देखने के बाद वीडियो डिलीट करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है? यह किसी से छिपा नहीं है कि वीडियो डाउनलोड करने वाला प्रेमी विकृत आनंद लेता है और लोगों को सच्चे प्यार का एहसास दिलाता है या वह पोर्न फिल्म डाउनलोड करता है और किस उद्देश्य से करता है। और यह अज्ञानता नहीं है, शायद प्रेमी उस समय इसका विरोध भी करे। लेकिन अगर प्रेमी को इस पर विश्वास नहीं है, तो दृढ़ता से विरोध करने के बजाय, उसे इस पर विश्वास करना ही होगा। यही प्रेमी का स्वभाव है। क्या वह प्रेमी जो मानता है कि वह बलात्कारी नहीं है, अपने साथी के मन के बारे में थोड़ा भी जान सकता है? और अगर प्रेमी का इरादा बुरा है, तो अंत में प्रेमी के पास अपने फैसले पर पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।

जब कोई प्रेमी निजी पलों का वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो प्रेमी को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। क्योंकि वहां कोई और मौजूद नहीं होता। अगर इस बुराई को रोका जाए, तो कई प्रेमी न केवल ब्लैकमेल होने से बचेंगे, बल्कि शीघ्रपतन के कारण आत्महत्या करने से भी बचेंगे । अब ऐसा लगता है किनिजी पलों की रिकॉर्डिंग पर तत्कालप्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

साबरमती स्टेशन पर रिडवलपमेंट कार्य के संबंध में ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

जीएनएस)। अहमदाबाद मंडल के साबरमती स्टेशन पर रिडवलपमेंट कार्य के संबंध में प्लेटफॉर्म नं. 01 पर इंजीनियरिंग कार्य हेतु 27-28 फरवरी 2026 को ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण कुछ पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

आंशिक निरस्त ट्रेन

27 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस आबूरोड-साबरमती के बीच आंशिक रद्द रहेगी।

28 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस साबरमती-आबूरोड के बीच आंशिक रद्द रहेगी।

पूर्णतः निरस्त ट्रेनें

27 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 79435/79436 साबरमती-पाटन-साबरमती डेमू रद्द रहेगी।

27 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 69249/69250 साबरमती-कटोसन रोड-साबरमती मेमू रद्द रहेगी।

ट्रेनों के ठहराव, मार्ग और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.inपर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।